(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें इस योजना का लाभ पहुँचने की संभावना है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के बीच हुए समझौते का बिहार द्वारा विरोध किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा बाणसागर परियोजना (यूनिट एक) बांध और आनुषंगिक निर्माण-कार्यों को 91.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अगस्त, 1978 में अनुमोदित किया गया था।

इस परियोजना में मध्य प्रदेश के देवलैंड गांव में सोन नदी के ऊपर .63 मीटर उच्च चिनाई-सह-राक फिल बांध का निर्माण करना परिकल्पित है और 4.00 मिलियन एकड़ फुट उपयोज्य जल-संचयन होगा। इसकी लागत और उपयोज्य जल-संचयन को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागीदार राज्यों द्वारा 2:1:1 के अनुपात में बांटा जाएगा।

(घ) से (च) बिहार सरकार से केन्द्र को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

Shortfall in Wheat Production in Punjab

1149. SHRIMATI PRAMILA DANDVATE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there has been serious shortfall in the prduction of wheat due to agitations in Punjab ;

(b) whether Government have assessed the situation ; and

(c) if so, the present position of wheat stocks and buffer stocks ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) No, Sir. Production of wheat in Punjab has been increasing during the past few years as may be seen from the Table below :

Production of Wheat in Punjab

(lakh tonnes)

1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (Provisional)
76.8	85.5	91.8	94.0

(c) The total wheat stocks with the Central and State Governments is estimated at 169.6 lakh tonnes (as on 1.7.1984), as against 130.1 lakh tonnes a year ago. This includes 50 lakh tonnes of buffer stocks.

देश में आवासीय इकाइयों की भावी आवश्यकता

1150. **श्री बापूसाहिब परूलेकर :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के सर्वेक्षण प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि देश को 1990 तक 90 लाख आवासीय एककों की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस प्रकार के मामले में, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा तैयार किए गए अनुमानों से सरकार को मार्ग निर्देशन दिया जाता है। संगठन ने आवास की वर्तमान कमी को इस प्रकार आंका है :—

शहरी	57 लाख
ग्रामीण	181 लाख
योग :	238 लाख

(ग) आवास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) आवास के लिए पूंजी निवेश का स्तर पांचवी योजना में 600.92 करोड़ रुपये से लेकर छठी पंच-वर्षीय योजना में 1490.87 करोड़ रुपये तक बढ़ाना।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के आवास प्रयासों में समाज के निर्धन वर्गों को और आश्रयविहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देना।

(iii) चालू योजना अवधि के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) का पूंजी निवेश स्तर 600 करोड़ रुपये तक बढ़ाना। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को ब्याज की रियायती दर पर ऋणों का प्रावधान करना।

(iv) आवास के लिए 1982 में उपलब्ध बैंक ऋण 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1983 में 150 करोड़ रुपये करना।

(v) आवास में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं।

(vi) बड़े-बड़े शहरों में सहकारी सामूहिक आवास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, 9 राज्यों में अपार्टमैंट आनर्शिप एक्ट लागू किया गया है।